Regarding need to declare `climate change` as natural disaster-laid

श्री तीरथ सिंह रावत **(**गढ़वाल**):** हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका कृषि पर तत्काल प्रभाव पड़ रहा है फसल चक्र बढ़ते मौसम और मिट्टी की नमी में बदलाव आ रहा है। उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से पहाड़ी प्रांत है कुछ तलहटी और मैदानी इलाकों के साथ समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अधिकांश कृषि योग्य भूमि है। जैसे-जैसे जलवायु परिस्थितियों बदलता है उत्तराखंड में कुछ किसान लाभप्रदता बनाए रखने के लिए सरकार या गैर सरकारी संगठनों की मदद से नई फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कहीं महिलाओं और दलित किसानों के लिए संभव नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अब कीवी पौधों के वितरण पर सब्सिडी देती है लेकिन फल उगाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार और अन्य संगठन एक ओर जलवायु अनुकूलन पहल का सुझाव दे रहे हैं- वह है 'जड़ी बूटी और औषधीय फसलों की खेती। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जो गरीब किसानों महिला किसानों या दलित किसानों के पास होने की संभावना नहीं है। लोगों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद करने के लिए सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा जैविक खेती एक और उपाय है। इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी। फिंगर बाजार, मंडुवा, झंगोरा और बार्नयार्ड बाजरा जैसी स्वदेशी फसलों पर जोर दिया गया है। जो अधिक जलवायु लचीली फफूंदे प्रतिरोधी है। अक्सर सिंचाई के बिना उगाई जा सकती है। सीमांत किसान भी अधिक वर्षा के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में केवल 45% कृषि भूमि सिंचित है इसलिए अधिकांश लोग अपनी फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर है। ऐसे अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजना का समर्थन किया है। उत्तराखंड सरकार स्थानीय किसानों को बीच उर्वरक और भारी मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चल रही है। जंगल की आग और कम बारिश जैसी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूलित करने में असमर्थ है। हिमालय राज्य में छोटे किसानों को अपनी आजीविका खोने का जोखिम उठाना पड़ रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन को एक प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पड़ने वाले वित्तीय बोझ को वहन करने के लिए राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।